(2) Overcrowding in prisons, especially with reference to undertrial prisoners, should be given priority consideration and appropriate steps should be taken in this regard to reduce the number of undertrials.

(3) Efforts should be made to provide purposeful occupation to undertrials.

(4) State level committees of Jail Visitors should be constituted where they do not exist.

(5) The working of District level and State level review committees should be activated so as to identify reasons for delay in investigation or trial. The committees at the District level and the State level should meet at least once in three months and six months respectively to review the hard cases and to find out possible ways to help the undertrials.

(6) Law officers should be attached to jails on whole time or part time basis to enable undertrials to contest their cases properly.

(7) Separate arrangements in Camp Jails etc., could be made with lesser security arrangements for prisoners who court arrest in large number during agitations.

(8) The capacity of Borstal institutions should be augmented.

(9) Living conditions should be improved to the maximum extent possible within the State resources and the funds allocated by the Central Government.

(10) Jail staff should be given proper training and orientation.

एच0 एम0 टी घड़ियों की बिक्री के लिए एजेंसियां

7573. श्री बापुश सुरवाई : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977–78 में एच०एम०टी० घड़ियों की बिक्री के लिए देश के विभिन्न भागों में एजन्सियां देने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये गये थे ;

(ख) राज्य वार कितनी एजन्सियां दी गई ; और

(ग) उनमें से कितनी एजन्सियां प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों और आदिवासियों को दी गई और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये एजन्सियां दी गई हैं और उनके नाम और पतों का राज्य वार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति) : (क) जी हां । एच०एम०टी० घड़ियों की बिक्री के लिए अधिकृत स्टाकिस्टों और अधिकृत सब एजन्टों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे ।

(ख) नियुक्त किए गए अधिकृत स्टाकिस्टों की राज्यवार संख्या नीचे दी जाती है—

	राज्य	संख्या
1.	बिहार	4
2	उत्तर प्रदेश	11
3	हरियाणा	4
4	पंजाब	2
5.	राजस्थान	7
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्मू और काश्मीर	1
8.	पश्चिम बंगाल	7
9.	गोवा	1
10	भूटान	1
11.	उड़ीसा	3
12.	आसाम	4
13.	उत्तर पूर्वी राज्य	4

(ग) वित्तीय तथा तकनीकी क्षमताओं और ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुभव के अनुसार तथा एच0 एम0 टी0 घड़ियों की कुल खरीद के लिए आश्वासन देने पर नियुक्तियां की गई हैं । इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों तथा आदिवासियों को उनका इन समुदायों से संबंध रखने के कारण एजन्सी देने का प्रश्न ही नहीं उठता है और इस तरह एच0 एम0 टी0 ने इनके बारे में कोई आंकड़े इकट्ठे नहीं किए हैं ।

Launching a special Campaign for Rural Industrialisation

7574. SHRI AMARSINH V. RATHAW: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state: